(घ) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के बजट के दौरान उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये वर्ष 1991 से 1993 के बीच प्राप्त आवेदनों की संख्या और उनके निपटान की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:—

जिले का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटान की स्थिति (1-4-94 को)		
		जारी किये गये आशय पत्र	अस्वीकृत	वापिस लिये/ लाइसेंस जरूरी नहीं
1	2	3	4	5
सूरत	47	36	5	6
बड़ौदा/बडोदरा	68	45	15	7
अंकलेश्वर	—	—	—	—
वापी	—	—	—	—
भड़ौंच	86	63	11	11
वालसाड़	44	24	8	9

(घ) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों को जल्दी निपटाने का भरसक प्रयत्न किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय की क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में इनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा पूरी जानकारी दिये जाने पर भी निर्भर करता है।

लघु उद्योगों के विकास की दर

7040. श्री राम जेठमलानी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में लघु उद्योगों के विकास की दर क्या रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से लघु उद्योगों के विकास की दर में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुये लघु उद्योगों के विकास की दर में वृद्धि करने के कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कितने लघु उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के.

लिये लघु क्षेत्र की विकास दर नीचे दी गई है:-

लघु क्षेत्र में उत्पादन की विकास दर

वर्ष	प्रतिशत
1991-92	3.1
1992-93	5.6
1993-94	5.9*

*अप्रैल 93-सितम्बर 93 की अवधि के लिये अनुमान ।

मतदान

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1992-97 ने पांच वर्षों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; वर्ष-वार लक्ष्य इस प्रकार हैं:--

वर्ष-वार लक्ष्य

वर्ष	प्रतिशत
1992-93	5.0
1993-94	7.0
1994-95	9.1
1995-96	9.1
1996-97	9.1

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिये निर्धारित उत्पादन के वर्ष-वार लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

उत्पाद की विकास दर

वर्ष	प्रतिशत
1991-92	3.0
1992-93	5.0
1993-94	7.0

देश में लघु औद्योगिक क्षेत्र संख्या के बारे में लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके ।

बिहार में भारी उद्योगों की स्थापना

7041. **श्री नागमणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नीति राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार को, जो काफी पिछड़ा राज्य है, 1962 से निजी उद्योगों में से कोई बड़ा उद्योग नहीं दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार बिहार को अतिशीघ्र एक बड़ा उद्योग देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र या प्रदेश के औद्योगिकीकरण का उत्तर-दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है । केन्द्र सरकार जहां भी संभव होता है उनके प्रयासों में सहायता करती है । देश में कम औद्योगिकृत क्षेत्रों के आधार-भूत विकास और औद्योगिकरण के लिये भारत सरकार ने 1988 में एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की । इस योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है । योजना के तहत बिहार को छः केन्द्रों का आबंटन किया गया है । ये केन्द्र भागलपुर, दरभगा, हजारीबाग, बेगुसराय, मुज्जफरपुर और छपरा जिलों में स्थित है ।